



न्यायालय माननीय प्रशासनिक सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
 निगरानी 478-I-15
 प्र.क्र. आर--- / 118 / 2015 / टीकमगढ़

श्री. टी. टी. गुप्ता 15.
 वाच आज ति 4-3-15 को
 प्रस्तुत
 म.प्र. शास. प्रतिपार्थी
 केन्द्र ऑफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

4-3-15

भागीरथ पुत्र श्री भरोसे द्दीमर
 निवासी ग्राम लिधौरा तहसील लिधौरा
 जिला टीकमगढ़. म.प्र. - पार्थी
 बनाम

1. श्रीमती लाडकुवर पत्नी श्री तुलई
 निवासी ग्राम लिधौरा तहसील
 लिधौरा, जिला टीकमगढ़

2- म.प्र. शास- प्रतिपार्थी

प्रार्थना पत्र निगरानी विरुद्ध श्रवमान राजस्व निरीक्षक न्यायालय तहसील
 लिधौरा जिला टीकमगढ़ आदेश दिनांक 20-10-14 पारित प्र.क्र. 1/
 अ-12/14-15 अन्तर्गत धारा 50 रे. को.

श्रीमान जी,

पार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

- 1- यह कि, अधिनियम न्यायालय का सीमांकन आदेश संहिता में प्रयोज्य की जाने वाली विधि प्रक्रिया के प्रकाश में अनियमित तथा अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि, ग्राम लिधौरा उगड के सर्वे क्र 0431/1 रकबा 1.619 है 0 के सीमांकन किये जाने के पूर्व आस पास लगे सर्वे क्र 0 432/2 के अलावा अन्य सर्वे क्र 0 के सरहद्दी कूडको को सूचना दिये बिना उनको उपस्थिति में स्थल पर पार्थी द्वारा सीमांकन कार्यवहही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णयों में पारित विधिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-478-एक/2015

जिला टीकमगढ़

भागीरथ विरूद्ध लाडकुंवर व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक लिधौरा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	

3

hem:
(आर.के. जैन) 18/2/2019
सदस्य